1	2
	नमक क्षेत्र का विकास (नया)
	नमक कारखानों का विकास (नया)
	परियोजना रिपोर्ट सेल
	तोल एवं माप
	औद्योगिक क्षेत्र
	परियोजना विरूपण सेल
II.	खनिज विकास
क.	खान और भूविज्ञान विभाग
	गहन खनिज अन्वेषण सर्वेक्षण, खानों और भूविज्ञान विभाग का पुनर्गठन और विस्तार
	खदान सुधार योजना
	लघु खनन पट्टेदारों को ऋण
	खानों एवं खदानों के लिए पहुंच मार्ग
	फास्फेट खनन परिष्करण—झमारकोटरा
ख.	राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड शेयरों की खरीद

Scrutiny of Savings through various Subsidies

3366. SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the suggestion made by Dr. Ashok Mitra, West Bengal's Finance and Planning Minister at a press conference on 23rd January, 1978 that savings could also be made in respect of food subsidies (totalling about Rs 475 crores), export subsidies to big industrialists (Rs 150 crores) and that rail freight subsidy and the hidden subsidy through the banking system should also be subjected to a scrutiny; and

(b) if so, the reaction of Government thereon?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) Yes, Sir. These subsidies are indicated at appropriate places in the Budget Documents of 1978-79, relating to the Railways and the Central Government; there the correct figures relating to these subsidies are also shown.

(b) It is Government's policy to review all subsidies and to reduce them progressively. In doing so, the effects of such economies on commodity prices and the cost of living would be borne in mind. Besides, the rail freight subsidy has also been brought to the notice of Railway Convention Committee, 1973 which examined the social burdens on Indian Railways. The Ninth Report of the Committee contains recommendations in this regard, on which the Government is taking action.

केन्द्रीय सरकार द्वारा राजसहायता

3367. श्री गंगा भक्त सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1977–78 के दौरान समाज के विभिन्न श्रेणियों तथा वर्गों के लोगों को राज-सहायता के रूप में 100 करोड़ रुपये की राशि दी है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1970–71 से आज तक कुल कितनी धनराशि दी गई है ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए और समाज की पिछड़ी जातियों को किस प्रकार के लाभ दिये गये ; और

(घ) वर्ष 1978–79 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राजसहायता देने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) केन्द्रीय सरकार विशिष्ट प्रयोजनों के लिए राजसहायता देती है । उदाहरण के लिए खाद्यान्नों की बिक्री से प्राप्त हुई रकम की तुलना में उनकी आर्थिक लागत की अतिरिक्त रकम की प्रतिपूर्ति करने के लिए भारत के खाद्य निगम को अदायगी करने के लिए 1978–79 के बजट अनुमानों में खाद्य के मामले में 456.01 करोड़ रुपये की राज-सहायता की व्यवस्था की गई है । नियंत्रित कपड़े और वनस्पति तेल की कीमतों के संबंध मे आर्थिक सहायता देने के लिए 1978–79 के बजट अनुमानों मे क्रमश: 21 करोड़ रुपये तथा 8 करोड़ रुपये की राज-सहायता की व्यवस्था की गई है । खाद्यान्नों, खाने के नमक आदि के मामले मे रेलवे ऐसी दरों पर भाड़ा किराया लेता है जो परिवहन लागतों से कम होती है, और इस प्रकार इन वस्तुओं पर रेलवे भाडे मे आर्थिक सहायता दी जाती है, 1977–78 के दौरान खाद्यान्नों पर रेलवे भाडे के संबंध मे राज-सहायता का वित्तीय प्रभाव 40.88 करोड़ रुपये आंका गया है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई राज-सहायता के संबंध मे सूचना केन्द्रीय सरकार और रेलवे के वार्षिक बजट दस्तावेजों मे उपलब्ध है ।

(ग) चूंकि आर्थिक सहायता विशिष्ट प्रयोजनों के लिए मंजूर की जाती है, इसलिए इससे होने वाले लाभ सामान्यत: समाज की पिछड़ी जातियों सहित पूरे देश को मिलते हैं । ऊपर (क) मे उल्लिखित आर्थिक सहायता, खाद्यान्नों, वनस्पति तेल और नियंत्रित कपडे की कीमतों को कम करने मे सहायक होती हैं, और उसके लाभ इन वस्तुओं के सभी उपभोक्ताओं, विशेष कर समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित लोगों को पहुंचते हैं ।

(घ) राज-सहायता के संबंध मे सूचना, रेलवे, और केन्द्रीय सरकार के 1978–79 के बजट दस्तावेजों में उपयुक्त स्थानों पर दी गई है ।

Construction of Aerodrome between Tirunelveli and Tuticorin

3368 SHRI K. T. KOSALRAM: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to construct an Aerodrome in between Tirunelveli and Tuticorin, a major port, near Valland village; and

(b) if so, at what stage the matter stands?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

सरकारी खर्चे पर विदेशों में भेजे गए गैर-सरकारी व्यक्ति

3369. श्री हुकमदेव नारायण यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1977 से दिसम्बर, 1977 के बीच सरकारी खर्चे पर कितने गैर-सरकारी व्यक्ति विदेशों मे गये और किस उद्देश्य से ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Setting up of Printing Press in Agartala

3370. SHRI YADVENDRA DUTT: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Tripura State Government has written to United Bank of India intimating their rediness to be guarantor for a loans of Rs. 7 lacs to a pro C.P.I. (M) paper